नई दिल्ली, मंगलवार
21 अगस्त 2018
नोएडा
मूल्य ₹ 4.00
पृष्ठ 16+6=22

दैनिक जागरण

मेरा शुरू से ही ध्यान स्वर्ण पर था। मैंने अच्छी ट्रेनिंग की और भगवान ने मेरा साथ दिया। आज का दिन मेरे लिए अच्छा रहा। वोट खिलाड़ी के करियर का हिस्सा है। मैं रियो ओलंपिक में वोट के बाद और भी ज्यादा मजबूत हुई।
– विनेश फोगाट

www.jagran.com
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

केरल की बाढ़ को केंद्र ने गंभीर आपदा घोषित किया 11
कोहली के शतक से नंबर वन टीम की गिरफ्त में अंग्रेज 15

जेवर एयरपोर्ट के लिए किसान जमीन देने को राजी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : प्रदेश सरकार और जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने में जमीन न मिलने की बाधा अब दूर होने लगी है। छह गांवों के 400 किसान जमीन देने को राजी हो गए हैं। उन्होंने 382 हेक्टेयर जमीन के लिए जिला प्रशासन को अपनी सहमति दे दी है।

सरकार को एयरपोर्ट के लिए प्रथम चरण में 1351 हेक्टेयर जमीन चाहिए। जमीन अधिग्रहण के लिए 70 फीसद किसानों की सहमति जरूरी है। प्रशासन और प्राधिकरण जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उससे उम्मीद है कि शेष किसान भी इस सप्ताह के अंत तक सहमति दे देंगे। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इस माह के अंत तक 70 फीसद किसानों ने सहमति पत्र भर दिए तो अक्टूबर में एयरपोर्ट का शिलान्यास हो जाएगा। यमुना प्राधिकरण का दावा है कि 2022 में जेवर से जहाज उड़ान भरना शुरू कर देंगे। जेवर एयरपोर्ट के लिए तीन चरणों में 16 गांवों की पांच हजार हेक्टेयर भूमि ली जानी है। प्रथम चरण में 1351 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इस पर दो हवाई पट्टी विकसित हो जाएंगी। इसके बाद दो हवाई पट्टी दूसरे चरण में विकसित की जाएंगी। प्राधिकरण ने एयरपोर्ट के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, लेकिन किसानों ने जमीन की मुआवजा दर कम बताकर भूमि देने से इन्कार कर दिया। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लागू हो जाने के बाद किसानों की सहमति से ही जमीन ली जा सकती है। जमीन अधिग्रहण से पहले 70 फीसद किसानों की सहमति जरूरी है। जिला प्रशासन ने इसके लिए प्रभावित गांवों में कुछ दिन पहले शिविर लगाकर किसानों से सहमति मांगी थी। तब किसानों ने जमीन देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद प्राधिकरण चेयरमैन व प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त डा. प्रभात कुमार, सीईओ डा. अरुणवीर सिंह व जिलाधिकारी बीएन सिंह ने किसानों के साथ बैठक कर उन्हें समझाया। जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह ने भी किसानों से बातचीत की। जिलाधिकारी बीएन सिंह पिछले तीन-चार दिनों ने गांवों में कैंप कर रहे हैं।

यमुना प्राधिकरण में बैठे किसान ● जागरण

कुरैब के किसान अपने गांव की जमीन देने को तैयार

कुरैब गांव के किसानों की रन्हेरा में 176 हेक्टेयर भूमि है। सोमवार को ग्राम प्रधान निर्दोष कुमार के नेतृत्व में किसान प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह से मिले। किसान प्राधिकरण द्वारा बताई गई दर पर जमीन देने को तैयार हो गए। किसानों ने कहा कि बगल के गांवों में सस्ती दरों पर जमीन बिक रही है। प्राधिकरण भी उन गांवों में 15 लाख रुपये प्रति बीघा का मुआवजा दे रहा है। इसलिए कुरैब के किसान 23 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने को तैयार है। इसके अलावा कुरैब गांव की 480 हेक्टेयर जमीन है। यह जमीन एविएशन हब के लिए ली जानी है। एयरपोर्ट की दूरी गांव से नजदीक है। किसानों ने अपने गांव की जमीन एयरपोर्ट के लिए देने का प्रस्ताव सीईओ को दिया। सीईओ ने बताया कि इसके लिए थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। किसी गांव के एयरपोर्ट के बाहर कर कुरैब को शामिल कर लिया जाएगा। प्राधिकरण किसानों के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेगा। क्योंकि इससे जमीन मिलने की बड़ी बाधा दूर हो जाएगी। प्राधिकरण को एक साथ 480 हेक्टेयर भूमि मिल जाएगी।

जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्षेत्र में खुशहाली आएगी। प्राधिकरण की मुआवजा दर से हम सहमत है। एयरपोर्ट के लिए गांव के सभी किसान अपनी सहमति से जमीन देने को तैयार है। सिर्फ वे लोग विरोध कर रहे हैं, जिनकी मात्र एक-एक बीघा जमीन जा रही है। बड़े किसान जमीन देने को राजी है। हमने अपनी सहमति दे दी है।

निर्दोष कुमार, ग्राम प्रधान, कुरैब